

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:—175/2019/223 (2019/00175)

1. अम्बालाल पुत्र सुखदेव,
2. भागचंद पुत्र प्रहलाद,
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम माण्डियावर खुर्द तहसील अंराई, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकरण पुत्र नन्दा जाट, निवासी माण्डियावर खुर्द तहसील अंराई, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई, जिला अजमेर ।
3. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा ढसूक जरिये शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा ढसूक, तहसील अंराई, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस



अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 3.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 38/2016.

उपस्थित:—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हंगामीलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांक:— 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.5.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 47 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम गुन्दली, तहसील अंराई में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर मय नीव सीव के विभाजन होकर अलग-अलग खाता नंबर, खसरा नंबर, लगान आदि कायम न होने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की बुवाई जुताई को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर मय नीव सीव के विभाजन करवाकर अलग-अलग ख्याता नगर, खसरा नंबर व लगान आदि कायम कर बंटवारे की डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादी को

DR-
राजस्थान अपील प्राधिकारी
अजमेर

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी०न्याया० ने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.5.2018 को पारित कर वादी/रेस्पो० संख्या 1 का वाद डिक्री किया । अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी०न्याया० ने अपीलांटस को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी०न्याया० ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उन्होंने प्रतिवादी/अपीलांट को वाद का नोटिस दिये बिना एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अपीलांट को लोक अदालत का नोटिस दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । विवादित आराजी खसरा नंबर 47 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है । उक्त हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मय नीव सींव के विभाजन कर अलग-अलग खाता नंबर, खसरा नंबर, लगान आदि कायम किया जाना चाहिये था किन्तु अधी०न्याया० ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधी० पेश कर कथन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया एवं अपीलांटस के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 21.4.2019 को ग्राम मण्डियावर खुर्द में पटवारी हत्का के बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 22.4.2019 को किशनगढ़ जाकर निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 3.5.2019 को नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । अधी०न्याया० ने दिनांक 23.1.2017 को वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार, अंराई को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के निर्देश दिये थे जिस पर तहसीलदार ने विवादित भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा तैयार कर अधी०न्याया० को भिजवाया है जिस पर अधी०न्याया० ने पक्षकारान को सुनकर, सहमत होने के उपरांत वाद में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत निर्णय व डिक्री है । अपीलांटस ने वादी/रेस्पो० संख्या 1 को परेशान करने की नियत से अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित



राजसूच अपील प्राधिकारी
अजमेर

किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं । हम अपीलान्टस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते हैं । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी०न्याया० ने दिनांक 22.6.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, अंराई को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये थे । अधी०न्याया० के निर्देशों की पालना में तहसीलदार, अंराई द्वारा दिनांक 3.5.2018 को बंटवारा मय नक्शा तैयार कर अधी०न्याया० को भिजवाये गये हैं । तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होने के संबंध में कोई नोटिस जारी कर सूचित किया हो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादी उपस्थित मिला । उक्त मौका रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट प्रतिवादीगण/अपीलान्टस की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाकर अधी०न्यायालय को भिजवाई गई है । अपीलान्टस का यह भी कथन रहा है कि अधी०न्याया० ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखने के संबंध में अपीलान्टस को नोटिस जारी नहीं किये हैं । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी० न्याया० द्वारा प्रकरण को दिनांक 3.5.2018 को अटल सेवा केन्द्र सान्दोलिया में रखने के संबंध में नोटिस जारी किये हैं किन्तु उक्त नोटिस वादी रामकरण हस्ताक्षर एवं प्रतिवादी/अपीलान्ट संख्या 1 अम्बालाल को ही तामील कराये गये हैं जबकि प्रकरण में अन्य प्रतिवादी भागचंद पुत्र प्रहलाद भी पक्षकार है जिसे भी नोटिस तामील कराया जाना आवश्यक था । अधी०न्याया० समस्त पक्षकारों को कैम्प कोर्ट में प्रकरण रखने के संबंध में नोटिस तामील कराये बिना तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर राजस्व नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना नहीं कर वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी०न्याया० को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार अंराई से स्वयं द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को बंटवारा प्रस्ताव पर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

